THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): The East Coast Road in question is a State Highway. Its construction/development, therefore, rests with the State Government of Tamil Nadu as the Central Government is primarily concerned with the roads declared as National Highways only. However, improvement of Madras-Cuddalore section of East Coast Road (167 km) has been taken up by the S-tate Government under Asian Development Bank loan assistance. The •stimated cost of the work is Rs. 63 rore and present overall progress is 40 r cent.

इलाहाबाद में यमुना नदी पर पुल का निर्माण

232. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में यमुना नदी पर सड़क पुल के निर्माण-काय को शुरू करने में विलंब के क्या कारण हैं ;

(ख) निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई का क्या ब्यौरा है ?

जल-भतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) इलाहाबाद जिले में यमुना नदी पर एक नए सड़क-पुल के निर्माण को अनुमोदन दे दिया गया है और ऋण सहायता के बारे में ओवरसीज इकनामिक कोआपरेशन फंड (जापान) के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। ऋण की अपेक्षाओं के अनुसार, परियोजना का पूरक व्यावहार्यता अध्ययन और ब्यौरेवार इंजीनियरी अपेक्षित होती है, जिसके लिए कार्रवाई की जा चुकी है। ऋण को कार्यान्वयन अनुसूची के अनुरूप परियोजना का निर्माण कार्य अक्तूबर, 1996 तक शुरू करने और मार्च, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है ।

नई सड़क-नीति का कार्यान्वयन

233. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा देश में सड़क मार्गों के सुधार और विस्तार हेतु निजी क्षेत्र की भागीदार बनाने के लिए नई सड़क-नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रारूप की रूपरेखा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नई सड़क-नीति के कार्यान्वयन की घोषणा कब तक करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) (क) से (ग) सरकार विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क आधारित सुविधाओं को बी०ओ०टी० (निर्माण, प्रचालन और हस्तान्तरण) के आधार पर निर्माण, रख-रखाव और प्रचालित करने में निजी क्षेत्र को सहभागी बनाने पर विचार कर रही है। तथापि, इस संबंध में नीति एवं दिशा-निर्देशों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए इस स्तर पर कोई स्थिति विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती ।

Illegal activities of the "tuckers' Union

234. SHRI RAMD\S AGARWAL: Will the Minister of SU *FACE TRANSPORT be peased to su

(a) whether Governi; at's attention has been drawn to a newsitem pubished in the "Hindustan Time? of 6th November, 1994 captioned "Truckers" unions